पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर खट्टर साहब दाखिला नहीं मिलेगा तब कुढ़ेगा इंडिया

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट

'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' का प्रचार इतना विस्तृत रूप ले चुका है कि आज टैक्सी, बस और ऑटो के पीछे भी इस नारे का स्टिकर चिपका देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं यह नारा दिया और इसमें कोई शक नहीं कि ये आज मशहूर तो है पर सिर्फ वैसे ही जैसे मोदी की खुद की मशहूरी को विज्ञापनों और मीडिया का डेली डोज चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी कॉलेजों की ओर देखें तो एक कहावत खूब जमती है इस नारे पर, 'हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और"।

फरीदाबाद के नेहरू कालेज में एडमिशन के लिए आई रश्मी कुमारी विज्ञान में 89.8 प्रतिशत लाने के बावजूद अपनी किस्मत पर रो रही हैं। रश्मी ने बताया कि उन्होंने राजकीय महाविद्यालय तिगांव में दाखिला ले लिया है पर अब वो नेहरू कॉलेज में आना चाहती हैं क्योंकि ये उनके घर डबुआ कॉलोनी से कहीं नजदीक पड़ता है। पर वो ऐसा नहीं कर सकती, नए नियम के मुताबिक अगर किसी छात्र ने 5 कॉलेजों में आवेदन किया है और किसी एक कॉलेज की मेरिट लिस्ट में छात्र का नाम आ जाता है तो बाकी 4 कालेजों की मेरिट लिस्ट में छात्र का नाम नहीं आ सकता चाहे छात्र के नंबर 95 प्रतिशत ही क्यों न हों। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एक छात्र एक साथ सभी कालेजों में आवेदन करना चाहे तो उसके लिए केन्द्रीयकृत फार्म की सुविधा वर्ष 2004 से ही उपलब्ध है। वहां इस एक छोटे से परिवर्तन से बच्चों को होने वाली समस्यायों का लगभग सटीक समाधान हो गया है। तो क्या महर्षि दयानंद विश्विद्यालय इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपना सकता?

19 वर्षीय अनुभव भी व्यवस्था की कुव्यवस्था और तरीकों से त्रस्त हैं। अनुभव अपने माता-पिता के साथ दाखिले को लेकर परेशान हैं। अनुभव ने बताया कि उन्होंने दो कोर्सों के लिए आवेदन किया था। आवेदन से पहले इस बात का ध्यान नहीं दिया कि नियम बदल गए हैं। नए नियम के मुताबिक यदि अनुभव ने दो कोर्स में आवेदन किया और पहली मेरिट लिस्ट में ही यदि किसी एक कोर्स में नाम आ गया तो अब किसी भी अन्य कोर्स में फिर दाखिला नहीं लिया जा सकता। अनुभव बीकॉम आनर्स में प्रवेश ले चुके हैं पर उन्हें लगता है वो पास कोर्स करना चाहते हैं। क्योंकि नियम में बदलाव हो चुका है तो अब उनके लिए अपने मन मुताबिक विषय चुनने की सहूलियत समाप्त हो गई है।

नेहरू कॉलेज फरीदाबाद में पढने वाले कमलेश बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। कमलेश के अनुसार (जिसे 'मजदूर मोर्चा' ने भी प्रकाशित किया था) पिछले साल भी इस प्रकार की समस्याओं से ही लगभग सभी बच्चों को गुजरना पड़ा था। उम्मीद थी कि इस बार प्रशासन पुरानी गलतियों से सबक लेगा पर इस बार भी हाल जस का तस है। कमलेश ने बताया कि पहले नियम था कि हरियाणा बोर्ड से बारहवीं किये छात्रों को वेरिफिकेशन नहीं कराना था, लेकिन अंतिम तिथि को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि हरियाणा बोर्ड वालों को भी वेरिफिकेशन करानी है। इससे हरियाणा के ही छात्रों का नाम मेरिट सूची में नहीं आ सका। वहीं कई छात्रों ने निजी कॉलेजों में वेरिफिकेशन नहीं कराई लेकिन बिना वेरिफिकेशन के भी कॉलेजों की तरफ से छात्रों को दाखिला कराने के लिए मेसेज आ रहे हैं। फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया था उस पर दाखिला सम्बन्धी कोई जानकारी मेसेज के माध्यम से नहीं दी गई।

फैजाबाद के सोहेल की जुबानी सुनें तो जामिया मिलिया में उन्होंने टूर एंड ट्रेवल में दाखिले के लिए अप्लाई किया। 120 सीटों के लिए 7000 बच्चों ने लिखित परीक्षा दी और 700 को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया है। पर्यटन में दाखिला सोहेल सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यही एक ऐसा कोर्स बचा है जिसकी फीस उनके अभिभावक भर सकते हैं अन्यथा वो बीटेक करना चाहते थे।

नयी शिक्षा नीति लागू करने के दावे के बीच पेश किये गए बजट के बाद भी वित्त मंत्री का ध्यान न ऐसे संगीन मुद्दों पर जाता है न जाएगा जहाँ एक युवा हताशा में डूबा हो सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि हमारी सरकारें उन्हें उनका मनपसंद विषय पढ़ने को नहीं दे सकतीं। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि जिस प्रकार के कोर्सेस आज विश्विद्यालयों में कराये जा रहे हैं उनसे रोजगार का कुछ खास नाता नहीं है।

खट्टर जैसे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं की शिक्षा को दरकिनार कर गौवंश की प्रतियोगिता केवल और केवल इसलिए कराने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर भी लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए न किसी प्रकार की मांग सरकार से कर रहे हैं और एक बड़ा तबका तो न ही इस मुद्दे की कोई अहमियत मानता है।

यूं तो पहले ही हमारे देश की शिक्षा नीति में उम्र की समय सीमा लागू की गई है, जहाँ एक उम्र के बाद यदि आप जागरूक हो भी जाएं तो भी सिवाय पश्चाताप के आपकी झोली में कुछ नहीं। ऊपर से यदि अब बच्चों को उनके मन मुताबिक विषय भी ना मिले तो ये क्या करें? एक तरफ समाज के ताने और प्रतियोगिता की होड़ और दूसरी तरफ सरकार की मार। अवसाद के अलावा हम क्या परोस रहे हैं अपने जिगर के टुकड़ों को? जो अब भी न जागे तो न पढ़ेगा और न बढेगा इंडिया, सिर्फ इस दौड़ में कुढ़ेगा इंडिया।

एनएसयूआई फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के सभी कॉलेजों के सभी कोर्स की बढ़ी हुई फीस के विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का आयोजन एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश सचिव कृष्ण अत्री की अगुआयी में किया गया।

कृष्ण अत्री ने बताया कि अबकी बार एमडीयू ने अपने सभी कॉलेजों के सभी कोर्स की फीस में 2000 से 3000 रुपये की बढ़ोतरी की है। ज्यादातर बढ़ोतरी स्नातक कक्षाओं में की गई है। अत्री की मानें तो नियम के अनुसार फीस बढ़ोतरी इस वर्ष से दाखिला लेने वाले बच्चों पर लागू होनी चाहिए लेकिन उच्चतर विभाग ने सत्र 2017 और 2018 में दाखिला लिए हुए छात्रों यानी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की फीस को भी दुगना करने का काम किया है।

आर्टस की सभी कक्षाओं में पहले एडमिशन फीस के रूप में लगभग 4400 रुपये लिए जाते थे लेकिन इस सत्र से लगभग 2600 रुपये की बढ़त करते हुए 6900 रुपये देने होंगे। वहीं विज्ञान की स्नातक कक्षाओं में लगभग 4400 रुपये फीस देनी पड़ती थी लेकिन इस सत्र से 7000 रुपये फीस देनी होगी तथा कॉमर्स की स्नातक कक्षाओं में 3400 रुपये फीस देनी पड़ती थी लेकिन इस सत्र से सभी में 6000 रुपये फीस देनी होगी। बीसीए की पहले 5620 रुपये फीस देनी पड़ती थीं लेकिन अब 8579 रुपये देनी होगी और बीबीए की पहले 5020 रुपये देनी होती थी लेकिन अब 7539 रुपये देनी होगी।

अत्री ने खट्टर सरकार और उच्चतर शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि खट्टर सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में तानाशाही नही दिखानी चाहिए। फीस बढ़ोतरी सिर्फ प्रथम वर्ष में ही नही बल्कि द्वितीय और तृतीय वर्ष में भी करने का क्या तुक है। पहले जितनी फीस छात्रों को प्रथम वर्ष में देनी पड़ती थी अब उससे भी कही ज्यादा द्वितीय और तृतीय वर्ष में भी देनी है। उन्होंने कहा कि वैसे तो फीस बढ़ोतरी ही सरासर नाजायज है लेकिन अगर फीस बढ़ोतरी लागू करनी भी है तो इस सत्र 2019-2020 के छात्रों पर लागू करें न कि सत्र 2017 और सत्र 2018 के दाखिला लिए हुए छात्रों पर, क्योंकि पिछले सत्र के छात्रों को फीस बढ़ोतरी के बारे में कोई जानकारी नही थी।

इस कदर फीस में बढ़ोतरी से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ रहा बल्कि उसका निजीकरण और व्यवसायीकरण हो रहा है। इस कारण शिक्षा मेहनतकश और वंचित तबकों की पहुंच से लगातार बाहर हो रही है। किसान, मजदूर परिवार के बच्चों का सरकारी कॉलेजों की तरफ ज्यादा रुझान रहता है क्योंकि यहाँ पर फीस प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में बहुत कम होती थी, लेकिन अबकी बार सरकार ने फीस दुगनी करके गरीब छात्रों से शिक्षा ग्रहण करने के हक को छीनने का ही काम किया है।

तृतीय वर्ष बीकॉम नेहरू कॉलेज की छात्रा शिखा ने बताया कि सरकारी शिक्षा संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं तक की बेहद कमी है। न पीने का साफ पानी मिलता है और न शौचालयों की उचित सफाई होती है। उसपर फीस बढाने के तर्क समझ से परे हैं। जब फीस बढ़ाई जा ही रही है तो कम से कम उचित सुविधाएं और पढने का माहौल तो दे सरकार। ऐसा लगता है जैसे जानबूझ कर हमें हतोत्साहित किया जा रहा हो कि या तो पढो ही मत और जो पढो तो सिर्फ प्राइवेट संस्थानों में। और ऐसे भी अगर पढ़ लिख भी लें तो कौन सी भला किसी को नौकरी मिलनी है।

जिस देश को विश्वगुरु बनाने का शगूफा खट्टर और मोदी सरकार ने छोड़ रखा है उसके युवा इतने हताश दिखने पर भी सरकार की नाकामियाँ इस कदर परवान चढ़ रही हैं कि मंगलवार को जारी पहली मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के अधिक नंबर थे उनका नाम ही नहीं आया और जिनके कम थे उनका नाम आ गया। इतना ही नहीं, सरकार ने 'पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढेगा इंडिया' जैसी शानदार पंच लाइनों से देशभर की दीवारें पाट दी हैं। पर इंडिया सिर्फ ये नारा ही पढ़ेगा या इसके आगे भी कुछ पढ़ेगा, इसका हिसाब सरकारें न देना चाहती हैं न देंगी।

दसियों ऐसे छात्रों और खास तौर पर छात्राओं से मिलकर मालूम पड़ा कि अच्छे नंबर लाने के बावजूद उनको वो विषय नहीं मिल रहे जिसमे उनका रुझान है। दीसी नामक एक छात्रा जिसके लगभग 91 प्रतिशत नंबर हैं को बीबीए में दाखिला चाहिए, उसे जबरन बीकॉम पकड़ा दिया है, इसी प्रकार चारु इतिहास आनर लेकर पढाई करना चाहती है पर उसे साइकोलॉजी दिया जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की समस्याओं का कोई निदान नहीं है पर निदान तो तब हो जब नीति बनाने और लागू करने वाले इसका समाधान खोजें या सोचें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा दूर नहीं, फरीदाबाद से सटी हुई है। वहां मात्र एक फॉर्म है जिसे भरकर बच्चा संतुष्ट हो सकता है और कटऑफ जारी होने की सूरत में जितने चाहे कालेजों या कोर्सों में उसका नाम आ जाए, दाखिला ले सकता है। तो फिर क्या कारण है कि एमडीयू छात्रों के लिए इस प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं कर सकता।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06